

सरपंच पति के चलन का एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनुराधा

राजनीतिक विज्ञान विभाग चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (भारत)

Date of Submission: 04-01-2021

Date of Acceptance: 19-01-2021

सार- महिला सशक्तिकरण के लिये शासन द्वारा नौकरियों से लगातार जनता के मध्यम से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के पदों में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73 वे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, पंचायतों में एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिये आरक्षित की गई थी। कई राज्यों ने आरक्षित सीटों की मात्रा पचास प्रतिशत तक बढ़ा दी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि महिलाओं की खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति और प्रचलित पितृसत्तात्मक स्थापना के कारण, पंचायत स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। राजनीतिक शक्ति और निर्णय लेने का काम निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों द्वारा किया जाता है, और इस घटना को सरपंच पति के रूप में जाना जाता है। सरपंच पति बैठकों में जाते हैं और महिला सरपंच को घूंघट में कैद करके रखा जाता है। जब तक

घूंघट रहेगा तब तक महिलाये आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिनमें बताया गया है कि सरपंच पति ग्राम पंचायत के सारे कामकाज में दखल देते हैं। साथ ही उन पर अभद्रता के आरोप भी लगाये गये हैं। कानून ने महिलाओं को अधिकार दिये हैं। जब कानून महिलाओं को अधिकार देता है तो उन्हें राजनीतिक नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिये। उन्हें सामाजिक, आर्थिक कार्यों के साथ-साथ राजनीतिक कार्यों में भी आगे बढ़ना चाहिये। पंचायतों में सीटों का आरक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये क्रान्तिकारी कदम था। परन्तु सरपंच पति प्रथा ने महिलाओं को पहले जहाँ थी वही लाकर खड़ा कर दी है। इसके लिये सरकार को सरपंच पति चलन को एक प्रभावी कानून के माध्यम से संबोधित करना चाहिये। शासन के मामले में क्षमता निर्माण पर आगे अतिरिक्त काम की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के महत्व के बारे में नौकर शाही को संवेदन शील बनाने की आवश्यकता है।

कीवर्ड्स- सशक्तिकरण, संवैधानिक संशोधन, पितृसत्तात्मक, नेतृत्व, सरपंच पति, आरक्षण, नौकर शाही, अभद्रता।

प्रस्तावना- किसी भी देश काल, समाज के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु सर्दियों में हमारे समाज में पुरुषों के अधीन रही है। हालांकि परोक्ष रूप से तो स्त्री को बराबर के अधिकार दिये गये हैं, देवी का दर्जा दिया गया है लेकिन वास्तविक रूप में तो सारे अधिकार अधिकतर गौण रूप में ही प्राप्त हैं। पुरुष प्रधान समाज में सारे कायदे कानून पुरुषों ने अपने हितों, अधिकारों और सुविधाओं को ध्यान में रख कर बनाये हुये हैं। वही स्त्रिया भी अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ हैं। विशेषकर अपने राजनीतिक अधिकारों और कर्त्तव्यों के

प्रति। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता में कमी देखी गयी है, खासकर ग्रामीण महिलाओं में इस दिशा में संविधान के

73 वे संशोधन के माध्यम से ग्रामीण व स्थानीय निकायों में क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जा सकता है। संविधान में 73 वे संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और महिलाओं के लिये पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो कुछ राज्यों में बढ़कर 50 प्रतिशत कर दी गयी है। हमारे संविधान के 73 वे संशोधन के कारण महिलाओं को गांव की राजनीति और शासन में जगह मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़ी संख्या में महिला प्रधानों को सरपंच पति या प्रधान पति नामक शर्मनाक प्रथा के द्वारा शवितहीन छोड़ दिया गया है।

यूनिसेफ की हालिया फील्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है, मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में 10 जिलों की अपनी रिपोर्ट में यूनिसेफ ने पाया कि 10 में 7 महिला प्रधानों को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं पता था। केवल 3 महिलाओं को पता था कि प्रधान के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारिया क्या है। इसका मतलब यह है कि भारत में यह आरक्षण 33: नहीं है जैसा कि संविधान द्वारा परिकल्पित किया गया है। गांव की राजनीति में महिलाओं के लिये बमुश्किल 3: ही सही प्रतिनिधित्व है यह तथ्य कि ये सरपंच पति खुले तौर पर संचालित होते हैं और सरकारी अधिकारियों प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस से मिलते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रणालि को सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह समस्या बहुत उम्र है इसमें और लगातार जारी है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने इस प्रथा से निपटने की कोशिश की है लेकिन इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं कारण यह है कि हमारी नौकर शाही के पास सरपंच पति चलने के लिये स्वीकृति है और किसी के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जा रहा है। **सरपंच पति या प्रधान पति चलन क्या है—** सीधे शब्दों में कहे तो महिला सरपंच का वह पति जो स्वयं प्रधान के रूप में सरपंच की सभी जिम्मेदारियां व भूमिका को निभाता है। सरपंच के सभी निर्णय स्वयं लेता है, सरपंच पति कहलाता है, महिला प्रधान केवल कागज पर मौजूद है एक बार चुने जाने के बाद उन्हे दरकिनार कर दिया जाता है और उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा एक मूक दर्शक बनाकर छोड़ दिया जाता है, सरपंच पति ही बैठकों का अध्यक्षता करते हैं, निर्णय लेते हैं, महिला सरपंच की ओर से उच्च अधिकारियों से मिलते हैं।

'सरपंच पति' को चलन के उद्भव के कारण— सरपंच पति के चलन के उद्भव के निम्नलिखित कारण हैं— **महिलाओं की खराब सामाजिक स्थिति—** हमारे समाज में स्त्रियों की बहुत निम्न दशा है। भारत में आज भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां स्त्रियों को पढ़ने-लिखने नहीं दिया जाता, उन्हे घर की चार दिवारी में और घूंघट में कैद करके रखा जाता है, जब तक घूंघट, रहेगा तब तक महिलाये आगे नहीं बढ़ सकती हैं। पंचायतों में 33: आरक्षण की आड़ में पुरुष द्वारा स्त्रियों को सरपंच के लिये चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है। और चुनाव जितने के बाद पुरुष द्वारा, उसके सभी राजनीतिक अधिकारों का उपयोग किया जाता है। स्त्रियां भी अपनी बचपन से निम्न दशा में पत्नी-बढ़ी होने के कारण पुरुष का विरोध नहीं कर पाती वे घरेलु स्थानों तक ही सीमित रहती हैं उन्हे पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने में भागीदारी की अनुमति भी नहीं है।

परंपरिक समाज के कारण सामाजिक बाधाये— गांवों में भारतीय समाज अभी भी पारंपरिक और रुद्धिवादी है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा की परंपरा बहुत मजबूत है विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर हतोत्साहित किया जाता है, यहा तक कि स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारी महिलाओं से बात करने से बचते हैं रुद्धिवादी दृष्टि कोण के कारण घूंघट जब महिलाओं पर लगाया जाता है, गंभीर रूप से उनकी सार्वजनिक भागीदारी में बाधा डालती है। इससे पंचायतों को दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में पति को वास्तविक नियंत्रण मिलता है यहां तक की ग्राम सभा की बैठकों में निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति प्रचार लेते हैं।

कौशल की कमी— अपनी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण या आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिये किसी भी चिता या प्रयासों को प्रदर्शित किये बिना महिलाओं के लिये आरक्षण को पचास प्रतिशत तक बढ़ाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है।

सरकार की पहल की अनुपस्थिति— 'सरपंच पति' चलन के बावजूद सरकार कानून के माध्यम से या सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से इसके खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रही है।

घरेलू हिंसा— घरेलू हिंसा भी सरपंच पति जैसी कूरीति के लिये जिम्मेदार है। पुरुष द्वारा महिला की मार-पिटाई कर उसे जबरदस्ती प्रधान पद के लिये खड़ा कर दिया जाता है, फिर जीतने के बाद सभी कर्तव्यों व अधिकारों का उपभोग उसके पति द्वारा किया जाता है।

'सरपंच पति चलन का प्रभाव— 'सरपंच पति' के चलन का हमारे समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है—

महिलाओं को सशक्त बनाने में विफलता— 'सरपंच पति' प्रथा या चलन महिलाओं के इच्छित सशक्तिकरण में बाधा डालती है जो सीटों के आरक्षण के माध्यम से 73 वे संवैधानिक संशोधनों में से एक था। महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में यथास्थिति बनाये हुये हैं जिस उद्देश्य से महिलाओं को आरक्षण दिया गया था कि महिलाये भी राजनीतिक कार्यों में भागीदार हो वह विफल रहा है।

कानून की अवमानना— यह प्रथा कानून के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से रोकते हुये उसकी अवमानना करती है। सरपंच महिलाओं के राजनीतिक कर्तव्यों व अधिकारों का उपभोग गैर कानूनी रूप से सरपंच पति द्वारा किया जाता है। **निर्णय लेने में अवसर की कमी—** सरपंच पति का चलन महिलाओं की ग्राम स्तर पर निर्णय लेने में भाग लेने की क्षमता को कम करती है। सरपंच पति द्वारा सरपंच महिला के सभी निर्णय लिये जाते हैं। पंचायतों की बैठकों में सरपंच महिला के पति द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है और महिला घूंघट में ही कैद होकर रह जाती है।

महिलाओं के शोषण में वृद्धि— इस प्रथा द्वारा सरपंच पति द्वारा कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें सरपंच महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित कर उसके कार्यों को जबरदस्ती अपने हाथों में लिये जाते हैं, इस प्रथा द्वारा महिलाओं के शोषण में वृद्धि देखी गयी है।

अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन— किसी भी शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के चयन परिकल्पना निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के लिये ठोस आधारों की आवश्यकता होती है यह ठोस आधार पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं, लेखों आदि से प्राप्त होता है। इसके लिये शोधार्थी को सन्दर्भ साहित्य के सर्वेक्षण की

आवश्यकता होती है। जो निम्नलिखित है। ईशा अग्रवाल की पुस्तक महिलाओं की राजनीति में बढ़ती सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण (2014) इसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को प्राप्त अधिकारों व सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी है या नहीं? इन सभी मुद्दों व समस्याओं के उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। 1. सुनील महावर की पुस्तक भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयान और चुनौतिया (2013) इसमें लेखक द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास से सम्बन्धित सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के संवर्ग में अध्ययन किया गया है और महिलाओं के अधिकार से सम्बन्धित कानून का भी वर्णन किया गया है। 3. सुनील कुमार की पुस्तक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एक विश्लेषण (2009) इसमें महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया है, उपर्युक्त सभी प्रस्तकों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व

राजनीतिक अधिकार का विश्लेषण किया गया है परन्तु सरपंच पति जैसी गंभीर प्रथा का इन सभी पुस्तकों या लेखों में बहुत ही कम विवेचन किया गया है। सरपंच पति जैसे गंभीर चलन का जितना विश्लेषण होना चाहिये ताकि इस जैसी कुरीति को समाज में कम किया जा सके, उतना नहीं किया गया है, अतः मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि सरपंच पति पर मेरे द्वारा किये अध्ययन तथा विश्लेषण से इस बुराई या कुरीति को समाज से मुक्ति मिलने में थोड़ा बहुत सहयोग मिल सके।

अध्ययन की शोध विधि— किसी भी अनुसंधान कार्य में शोध पद्धति का विशेष महत्व होता है, शोध मध्ययन को सार्थक और सत्य पर आधारित करने के लिये वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, प्रस्तुत अध्ययन सरपंच पति के चलन का सैद्धान्तिक, अनभवात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन है, मैंने प्रस्तुत अध्ययन में डॉक्ट्रिनल मेथड या सिद्धान्त पद्धति के लिये आंकड़े या डेटा पुस्तकालय पत्रिकाओं, केस कानून, समाचार पत्रों व इंटरनेट आदि से लिये हैं। समय—धन बचाने के लिये मैंने शोधकार्य हेतु सिद्धान्त पद्धति का उपयोग किया है। दूसरा यह पुस्तकालय पर आधारित है यह शोध के लिये कम खर्चीली व कम समय लेने वाला तरीका भी है। और अध्ययन की पद्धति मेरे अनुभव और किये गये विश्लेषण पर आधारित है।

निष्कर्ष व सुझाव— महिला सशक्तिकरण के लिये शासन द्वारा जनता के माध्यम से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के पदों में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हालात यह है कि मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पी यानि सरपंच पति काम काज की बागड़ोर संभाले हुये हैं। सरपंच पति ग्राम पंचायतों के सारे कामकाज में दखल करते हैं। साथ ही उनके द्वारा महिला सरपंच पर अभद्रता के आरोप भी देखे गये हैं। इतना ही नहीं वह पूरे समय पंचायत में सरपंच कुर्सी पर बैठकर कामकाज देखता है सरपंच पति द्वारा अनावश्यक दखल देकर शासन ने उस आदेश की भी धज्जिया उड़ाई जा रही है, जिसमें महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या अन्य रिश्तेदार कामकाज नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंचायतों में सरपंच पति संस्कृति समाप्त करने का आहवान करते हुये गरीबी उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रचार—प्रसार में निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों के लिये नेतृत्व वाली भूमिका की वकालत की सरपंच महिला के कामकाज में पतियों के कथित दखल के बारे में मोदी ने एक राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया। उनके अनुसार किसी ने उनसे कहा कि वह सरपंच पति प्रधानमंत्री ने कहा कि सरपंच पति का काम चल रहा है। कानून ने महिलाओं को अधिकार दिये हैं। जब कानून उन्हे अधिकार देता है तो उन्हे अवसर भी मिलना चाहिये। इस सरपंच पति संस्कृति को खत्म करे और महिलाओं के राजनीतिक भूमिका का अवसर दिया जाना चाहिये। उन्हे आगे बढ़ने देना चाहिये।

पंचायतों में सीटों का आरक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये क्रान्तिकारी कदम था। हालांकि इसके लिये प्रभावी सरकार को सरपंच पति की घटना को एक प्रभावी कानून के माध्यम से संबोधित करना चाहिये। महिलाओं की खराब सामाजिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिये, उन्हे पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने में भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिये। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिये। सरकार को पंचायतों में प्रधान पद के लिये निर्वाचित महिला के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। सरकार को पर्दा प्रथा पर रोक तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, देने वाले कार्यक्रम चलाने चाहिये। सरकार को सरपंच पति जैसी कुरीति को रोकने के लिये कठोर कानून बनाने चाहिये जिससे सरपंच पति जो महिला सरपंच के अधिकारों व कर्तव्यों का असवैधानिक रूप से निर्वहन करता है पर रोक लगाई जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

- 1- दंपकनदपंष्पवउ एसपी संभाल रहे पंचायतों की व्यवस्था' 22 रनस 2015
 - 2- पदकपंदमू पेण्बवउ ' दिल्ली का दंगल' 2020. 3. 'मम दमू हिन्दी
 - 4- वतपौजपैण्पवउ 'हिन्दी साहित्य: पेन ड्राइव कोर्स'
 - 5- डण्चंजतपबंण्बवउ 'मोदी ने कहा कि किसी भी गांव में बसने वाले लोग बड़े सपने देखते हैं 6.
- प्रौज्जन्म चेतना
- 7- प्रौज्जन्म चेतना
 - 8- डण्चंजतपबंण्बवउ प्रधानपति फोटो, प्रधानपति इमेज
 - 9- छंअईंतंजजपउमे प्रधानपति संजमेज प्रधानपति छमू — नदकंजमे चतंकींद ३ छंअईंतंज ज्यउमे 6 कमब 2019
 - 10- ईशा अग्रवाल की पुस्तक 'महिलाओं की राजनीति में बढ़ती सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण' (2014) 11. सुनील महावर की पुस्तक भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम और चुनौतियाँ' (2013) 12. सुनील कुमार की पुस्तक 'महिलाओं में राजनीतिक जगरूकता: एक विश्लेषण' (2009)
 - 13- 'प्रौज्जन्म चेतना' उपजपउमे वि पदकपंष्पवउ व्यतंकींद चंजप संजमेज दमूए अपकमवे दक चीवजवे वि चतंकींद चंजप
 - 14- अमर उजाला. कॉम
 - 15- प्रौज्जन्म चेतना प्रधानपति दमू पद वि पदकप प्रधानपति से जुड़ी खबर 16. प्रौज्जन्म चेतना

सरपंच पति के चलन का एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन

- प्रैपदकपण्डमूण्बवउ अलीगड़ प्रधान पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या 17. 'मम दमौण प्दकपण्बवउ कानपुरः प्रधानपति की घर के पास गोली मारकर हत्या
- 18- प्रैजजचेरुद्धूण्डुतनरंसंष्बवउ चतंकींद ॑नेइंदक उनतकमत इल प्रैववजपदह पद
हींपचनत 19 उंत 2019
- 19- प्रैजजचेरुद्धूण्डुंजतपबंण्बवउ चतंकींद ॑नेइंदक ॑दक'वद पिहीजूपजी अपससंहमते
20- प्रैजजचेरुद्धूण्डुण्जंजतपबंण्बवउ पंचायतो से सरपंच पति कल्वर खत्म करने की जरूरतमोदी 24। चत 2015
21- भ्यदकपण्वदमपदकपण्बवउ रोचकः ये हैं दो बीवी वाले, प्रत्याशो, सरपंच पद के लिये एक 10 श्रंद
2020